ग्रामीण विकास विभाग को ई-गवर्नेंस का पुरस्कार

राज्य ब्यूरो, पटना : ग्रामीण विकास विभाग को ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह प्रथम पुरस्कार इसे इंदिरा आवास योजना में ऑनलाइन बहाली की प्रक्रिया अपनाने के लिए दिया गया है। 30 एवं 31 जनवरी को दिल्ली में आयोजित 18वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार के लिए बिहार के ग्रामीण विकास विभाग का चयन करने के क्रम में कहा गया है कि इंदिरा आवास योजना में 9770 कर्मियों की बहाली में बहुत बेहतर पारदर्शिता अपनाई गई है। विभाग ने बहाली के लिए संविदा के नाम से विशेष साफ्टवेयर बनाया था। पिछले कुछ सालों में विभाग को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पिछले साल फरवरी में मनरेगा में पारदर्शिता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था। साथ ही कन्वर्जेंस के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था।

यह बिहार के लिए गौरव का क्षण है। विभाग ने पिछले चार सालों में मेहनत कर सुशासन के कार्यों को धरातल पर उतारा है। यह पुरस्कार उसी मेहनत का नतीजा है।

-नीतीश मिश्रा, ग्रामीण विकास मंत्री